भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान, मुख्यालय - ग्वालियर से संचालित

दैनिक पर्यटन समाचार

IITTM पर्यटन शिक्षा संस्कृति रक्षा

दिनांकः रविवार 29 अगस्त 2021 संपादकः प्रो. (डॉ.) आलोक शर्मा, निदेशक, भापयाप्रसं पृष्ठ 1

"सफल होने के लिए महज एक शक्तिशाली सकारात्मक विचार ही काफी है...!"

रविवार विशेषांक

सभी पाठकों को सादर नमस्कार!

प्रिय पाठकों, आज के रविवार विशेष अंक में प्रस्तुत है केन्द्र सरकार द्वारा **'राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन' (नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन) योजना पर एक नज़र!**

केन्द्र सरकार ने 'राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन' (एनएमपी) लॉन्च की है। इस कार्यक्रम को लांच करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आने वाले चार सालों यानी की 2021 से 2025 के बीच में सरकार को इससे 6 लाख करोड़ रुपये की इनकम होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि सरकार केवल अंडर-यूटिलाइज्ड एसेट्स को ही बेचेगी। इसका हक सरकार के पास ही रहेगा और प्राइवेट सेक्टर के पार्टनर्स को तय समय के बाद अनिवार्य रूप से वापस करना होगा।

क्या होता है एसेट मोनेटाइजेशन

संपत्ति मौद्रिकरण का अर्थ सरकारी क्षेत्र की उन संपत्तियों से राजस्व या आय के नए साधनों के रास्ते खोजना है जिनका अब तक पूरा दोहन नहीं किया गया है। सरकार पूंजी की किल्लत से जूझ रही है इसलिए सरकार चाहती है कि निजी कंपनियां पैसे लगाए। कई सरकारी कंपनियां, प्रोजेक्ट लचर प्रबंधन, पूंजी की किल्लत, तकनीकी अक्षमता से जूझ रही है।

कौन-कौन से सेक्टर में है सबसे ज्यादा एसेट मोनेटाइजेशन

केंद्र सरकार ने एसेट मोनेटाइजेशन के लिए नीति आयोग को जिम्मेदारी दी थी। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे, सड़क परिवहन और हाईवे, जहाजरानी, टेलीकॉम, बिजली, नागरिक उड्डयन, पेट्रोलियम और नैचुरल गैस, युवा मामले और खेल में एसेट मोनेटाइजेशन है।

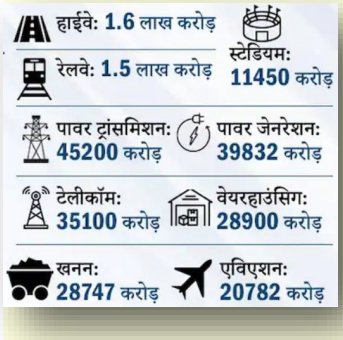

कहां से कितना पैसा मिलेगा

पीटीआई के अनुसार सरकार रेल सेक्टर से स्टेशन, ट्रैक, पैसेंजर ट्रेन, कोंकण रेलवे को मोनेटाइज करने वाली है। इससे चार साल में 1.52 लाख करोड़ मिलेंगे। सड़कों के मोनेटाइजेशन से केंद्र को 1.60 लाख करोड़ मिलेंगे। बिजली से केंद्र सरकार को 45200 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। टेलीकॉम सेक्टर से सरकार को 35100 करोड़ रुपये मिलेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 25 हवाई अड्डों को निजी कंपनियों को देने जा रही है। इससे सरकार को 20782 रुपये मिलने वाले हैं।

वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ किया

केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बीते सप्ताह 23 अगस्त 2021 को 'राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी खंड

संपादक मण्डल - डॉ. सौरभ दीक्षित, डॉ. चन्द्रशेखर बरूआ. समाचार संग्रह व प्रस्तुति-मयंक दुबे. डिजाइन - दीपक मित्तल

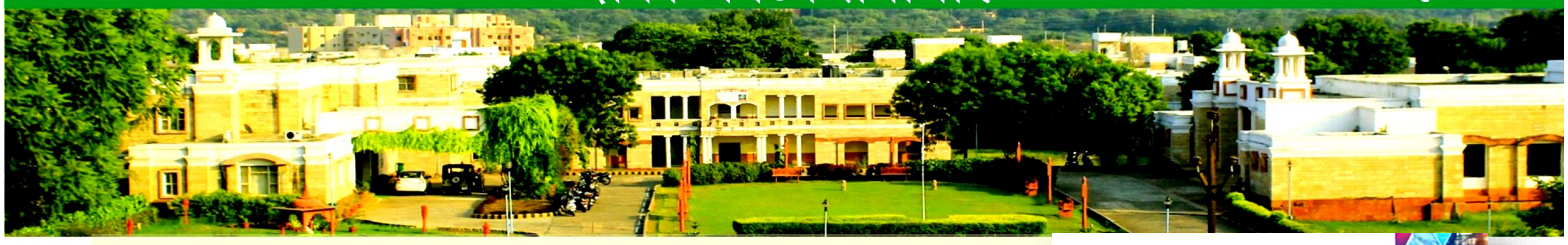

1 और 2)' का शुभारंभ किया जो केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परिसंपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन है। यह पाइपलाइन नीति आयोग द्वारा अवसंरचना से संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से विकसित की गई है जो केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत 'परिसंपत्ति मुद्रीकरण'से जुड़े अधिदेश पर आधारित है। एनएमपी के तहत वित्तीय वर्ष 2022 से लेकर वित्तीय वर्ष 2025 तक की चार साल की अवधि में केंद्र सरकार की मुख्य परिसंपत्तियों के जरिए 6.0 लाख करोड़ रुपये की कुल मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया गया है।

एनएमपी पर रिपोर्ट के खंड 1 और 2 को आज उपाध्यक्ष (नीति आयोग), सीईओ (नीति आयोग) और पाइपलाइन के तहत शामिल अवसंरचना से संबंधित मंत्रालयों यथा सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग, रेलवे, बिजली, पाइपलाइन व प्राकृतिक गैस, नागरिक उड्डयन, पोत परिवहन, पत्तन एवं जलमार्ग, दूरसंचार, खाद्य व सार्वजनिक वितरण, खनन, कोयला और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालयों के सचिवों के साथ-साथ सचिव (आर्थिक कार्य विभाग) और सचिव (निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) की उपस्थिति में जारी किया गया।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने पाइपलाइन का शुभारंभ करते हुए कहा, 'परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम हमारे माननीय प्रधानमंत्री के विजन से ही सटीक स्वरूप ले पाया है, जो सदैव भारत के समस्त आम नागरिकों के लिए बेहतरीन और किफायती बुनियादी ढांचागत सुविधाओं तक पहुंच में विश्वास करते हैं। मुद्रीकरण के माध्यम से सृजन के दर्शन पर आधारित परिसंपत्ति मुद्रीकरण का उद्देश्य नई बुनियादी ढांचागत सुविधाओं या अवसंरचना के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र के निवेश का उपयोग करना है। यह रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है जिससे आर्थिक विकास की गति को तेज करने के साथ-साथ समग्र जन कल्याण के लिए ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को निर्बाध रूप से एकीकृत करना भी संभव हो सकेगा।'

नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने इस पाइपलाइन के शुभारंभ के दौरान कहा, "इस कार्यक्रम का रणनीतिक उद्देश्य संस्थागत और दीर्घकालिक पूंजी का उपयोग करके सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदा (ब्राउनफील्ड) परिसंपत्तियों में निहित निवेश के मूल्य को हासिल करना है, जिसे आगे सार्वजनिक निवेश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने इस तरह से निवेश के मूल्य को हासिल करने के तौर-तरीकों पर विशेष जोर दिया, जिसे निजीकरण या औने-पौने मूल्यों पर परिसंपत्तियों को बेचने के बजाय व्यवस्थित अनुबंधात्मक साझेदारी के जरिए प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है।"

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन: एक परिचय

केंद्रीय बजट 2021-22 में स्थायी अवसंरचना निर्माण के वित्तपोषण के लिए वर्तमान में संचालित की जा रही सार्वजनिक अवसंरचना परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की पहचान एक प्रमुख साधन के रूप में की गयी है। इसके लिए बजट में ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों के सन्दर्भ में 'राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी)' तैयार करने का प्रावधान किया गया है। नीति आयोग ने अवसंरचना से जुड़े मंत्रालयों के परामर्श से एनएमपी पर रिपोर्ट तैयार की है।

एनएमपी का उद्देश्य सार्वजनिक परिसंपत्ति के मालिकों के लिए इस कार्यक्रम के सन्दर्भ में एक मध्यम-अवधि रोडमैप प्रदान करना है। इसके साथ ही निजी क्षेत्र की परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग के लिए उनकी वर्तमान स्थिति तथा संभावनाओं के बारे में भी जानकारी दी गयी है। एनएमपी पर रिपोर्ट को दो खंडों में बांटा गया है। खंड-I एक मार्गदर्शन पुस्तिका के रूप में है, जिसमें परिसंपत्ति मुद्रीकरण के वैचारिक दृष्टिकोण और संभावित मॉडल का विवरण दिया गया है। खंड-II में मुद्रीकरण के लिए वास्तविक रोडमैप दिया गया है, जिसमें केंद्र सरकार के तहत मुख्य अवसंरचना परिसंपत्तियों की पाइपलाइन शामिल है।

ढांचा

पाइपलाइन को संबंधित मंत्रालयों और विभागों से इनपुट और परामर्श के आधार पर तैयार किया गया है, साथ ही उपलब्ध कुल परिसंपत्ति का आकलन भी किया गया है। विनिवेश के माध्यम से मुद्रीकरण और गैर-प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण को एनएमपी में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, वर्तमान में, केवल केंद्र सरकार के मंत्रालयों और अवसंरचना से जुड़े केन्द्रीय उपक्रमों (सीपीएसई) की परिसंपत्तियों को शामिल किया गया है। अभी राज्यों की परिसंपत्तियों के समन्वय और आकलन की प्रक्रिया चल रही है और इन्हें उचित समय पर शामिल करने की परिकल्पना की गई है।

अनुमानित क्षमता

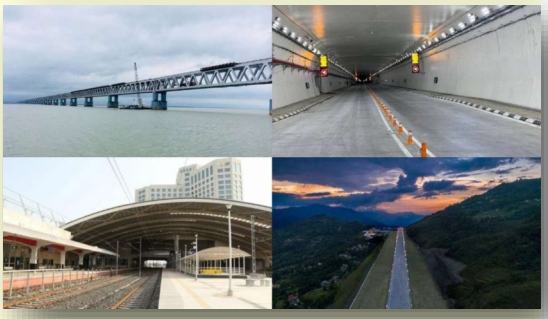

अवसंरचना का निर्माण मुद्रीकरण से अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है, इसे ध्यान में रखते हुए एनएमपी के लिए समय तय किया गया है जिससे राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) के अंतर्गत शेष अवधि साथ-साथ समाप्त हो जाए।

चार साल की अवधि यानी वित्त वर्ष 2022-25 के दौरान एनएमपी के अंतर्गत कुल संपत्ति का अनुमानित मूल्य 6.0 लाख करोड़ रुपये है। यह अनुमानित मूल्य केंद्र द्वारा एनआईपी के अंतर्गत प्रस्तावित परिव्यय (43 लाख करोड़ रुपये) का 14 प्रतिशत है। इसमें 12 से ज्यादा संबंधित मंत्रालय और 22 से ज्यादा संपत्ति श्रेणियां शामिल हैं। सेक्टरों में सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेलवे, वेयरहाउसिंग, गैस और उत्पाद पाइपलाइन, बिजली उत्पादन और पारेषण, खनन, दूरसंचार, स्टेडियम, हॉस्पिटैलिटी और आवास शामिल हैं।

कार्यान्वयन और निगरानी व्यवस्था

समग्र रणनीति के रूप में, संपत्ति आधार का बड़ा हिस्सा सरकार के पास रहेगा।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य 'मुद्रीकरण के माध्यम से अवसंरचना निर्माण' को संभव बनाना है, जिसमें क्षमता के लिहाज से अपने-अपने क्षेत्रों के उत्कृष्ट सार्वजनिक और निजी क्षेत्र सहयोग करें, जिससे सामाजिक आर्थिक विकास को संभव बनाया जा सके और देश के नागरिकों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो।

संस्थान समाचार

आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान (आईआईटीटीएम) में वर्ष भर होने वाले आयोजन को लेकर आज 29 अगस्त 2021 शाम 6:30 आईआईटीटीएम थिएटर क्लब 'चश्मा नाट्य गुट' और फिल्मकथा स्टूडियो की संयुक्त प्रस्तुति धनूआ का मंचन संस्थान के ऑडिटोरियम में किया जा रहा है।

आप सभी का स्वागत है, जरुर पधारें!

मुद्रा अद्यतन (##)

मुद्रा	मूल्य ₹
1 USD (US$)	73.48
1 EURO (€)	86.69
1 GBP (£)	101.11
1 JPY (¥)	0.669
1 AUD (A$)	53.74

(##) सभी आंकड़े लाइव मिड-मार्केट रेट हैं, जो उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं हैं और केवल सूचना के उद्देश्य से हैं।

आप 'दैनिक पर्यटन समाचार' में पर्यटन विषय पर अपने लेख/विचार एवं अपने बहुमूल्य सुझाव देने के लिये हमें संपर्क कर सकते हैं। ईमेल द्वारा: social@iittm.ac.in व्हाट्सएप द्वारा: +91 70427 30070

#आज़ादीकाअमृतमहोत्सव #जयहिंद आपका दिन शुभ हो...।

@IITTMOFFICIAL @iittmofficial @IITTMOfficial

अस्वीकरण: भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान, ग्वालियर मुख्यालय द्वारा प्रस्तुत 'दैनिक पर्यटन समाचार' का मूल उद्देश्य पर्यटन अकादमिक जगत को दैनिक आधार पर हो रही घटनाओं व गतिविधियों से रूबरू कराना है, चूँकि पर्यटन जगत बहुत 'गतिक' (डायनेमिक) है। इस समाचार पत्र का स्त्रोत आधार विभिन्न सूचना माध्यमों से प्राप्त सम्प्रेषण है। अतः इनकी पुष्टि, संस्थान व संपादन मंडल नहीं करता है। हालांकि अकादमिक हित में इसकी प्रस्तुति केवल ज्ञान उन्नयन हेतु की जाती है।